(ङ) और (च) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के वर्षों के लिए गेहूं की इकनामिक लागत निम्नानुसार है:-

(रुपए प्रति क्विंटल)

| वर्ष | इकनामिक लागत |
|---|---|
| 1992-93 | 504.10 |
| 1993-94 | 559.40 |
| 1994-95 (बजट अनुमान) | 563.57 |

**बिहार में चीनी मिलें**

4277. **श्री आस मोहम्मद:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में कुल कितनी चीनी मिलें चलाई जा रही हैं;

(ख) इनमें से क्षेत्र-वार कितनी मिलें लाभ कमा रही हैं और कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं;

(ग) रुग्ण मिलों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सहकारी क्षेत्र की घाटे में चल रही चीनी मिलों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय):** (क) बिहार में 30 संस्थापित चीनी मिलें हैं। इन 30 मिलों में से 15 गैर-सरकारी क्षेत्र और 15 सरकारी क्षेत्र में हैं।

(ख) यह मंत्रालय चीनी मिलों से संबंधित लाभ और घाटे का कोई हिसाब नहीं रखता है।

(ग) चीनी मिलों को पुनर्वास/आधुनिकीकरण की योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती हैं और उनका वित्तीय संस्थाओं से अनुमोदन कराना होता है। ऐसी पुनर्वास/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि (एस॰डी॰एफ॰) से रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों।

(घ) और (ङ) इस संबंध में नीति तैयार करना संबंधित रुग्ण चीनी मिलों/राज्य सरकारों का काम है।

**Export of Foodgrains**

4278. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the extent of the availability of foodgrains at present in Government godowns and under what consideration Government have taken a decision to export the same;

(b) whether Government had made any assessment about the profit or loss likely to be earned or incurred from the export of wheat before taking such a decision;

(c) if so, what are the details of the assessment made in this regard;

(d) whether Government would review the proposal regarding export of foodgrains in case the money earned through such export is likely to be less than the economic cost of Food Corporation of India;

(e) whether there is any proposal under Government's consideration to sell the surplus foodgrains through Public Distribution System to poor, backward and tribal regions of the country; and

(f) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (d). The stock of foodgrains (wheat and rice) in Central Pool as on 1.7.1994 was as under:

(In lakh tonnes)

| | |
|---|---|
| Wheat (P) | 164 |
| Rice (P) | 133 |

(P) Provisional

No decision to export foodgrains from Central Pool has yet been taken.

(e) and (f) Already revamped Public Distribution System (RPDS) is in operation to distribute the foodgrains among the poor, backward and tribal regions of the country at a specially subsidised rate which is less by Rs. 50/- per quintal than the rate prescribed for normal PDS.

**Setting up of Sugar Factories in Co- operative Sectors**

4279. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FOOD be pleased to state: